Statement-II

Sector wise allocation of Plan outlay for the Annual Plan 1994 95 of Gujarat

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Sector	Annual Plan 1994 95 Approved Outlay
1.	Agriculture & Allied Activities	13330.50
2.	Rural Development	8195.50
3.	Special Area Programmes	0.00
4.	Irrigation & Flood Control	39683.00
5.	Energy	49890.00
6.	Industry & Minerals	12597.50
7.	Transport	10217.00
8.	Communications	165.00
9.	Science, Technology & Environment	105.00
10.	General Economic Services	4366.50
11.	Social Services	65382.00
12.	General Services	68.00
	TOTAL :	224000.00

हानि में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम

3223. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगातार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिये कोई नीतिगत फैसला लिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस योजना पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर) गमंग) : (क) 1991-92 से 1993-94 तक के पिछले 3 वर्षों में 83 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे हैं ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनः स्थापन और उनके कार्य में सुधार हेतु और आधुनिकीकरण और विविधीकरण स्कीमों के माध्यम से उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) घाटे में चल रहे उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की गई है । इनमें से प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाता है । और उनके लिए वार्षिक योजनाओं में उपयुक्त प्रावधान किए जाते है।

Classification of Hill Areas in the States

3224. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION bo pleased to states:

(a) whether it is a fact that a Technical Committee of the Working Group constituted by the Planning Commission in the last decade made suggestion about the classification of hill areas in the States;

(b) if so, whether the hill areas have been identified according to this definition;

(c) what are the hill areas identified in Madhya Pradesh as per the recommendations of the Technical Committee; and

(d) whether these areas will be considered for central assistance on par with the hill areas of the border States?